The financial institutions provide assistance to entrepreneurs in Rajasthan on the same basis as in other States. The investment of financial institutions is dependant on the extent of entrepreneurial activity generated.

16 districts of Rajasthan have already been declared as industrially backward to qualify for concessional finance and other facilities. The State is already identified as an industrially backward State, and accordingly six districts have been selected to qualify for the Central Investment Subsidy Scheme.

विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतन का संरक्षण

3447. श्री रामदेव सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समाचार एजेंसियो के कर्मचारियो के वेतन आदि के संरक्षण के बारे मे सरकार द्वारा संसद् में दिए गए आश्वासनो की क्रियान्विति के लिए सरकार और प्रेसट्रस्ट, यूनाइटिड न्यूज हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारती के प्रबन्धको के बीच लिखित अथवा मौखिक समझौता हुआ है और यदि हां तो क्या इसकी क्रियान्विति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) क्या सभी चार एजेंसियो को 'समाचार' द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ को वापिस लिए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जैसा कि 14 नवम्बर, 1977 को ससद् में दिए गए वक्तव्य के पैरा 6 में निहित है सरकार भूतपूर्व 'समाचार' के, कर्मचारियों की परिलब्धियो का सरक्षण करने मे सहायता करने और समाचार में उनके द्वारा ली जाने वाली परिलब्धियो तथा यदि वे अपनी मूल एजेंसियो में काम करते रहते तो उनको जो परिलब्धियां मिलती, उनके बीच के अन्तर की पूर्ति करने के लिए चार समाचार एजेंसियो को क्रमिक ह्रासाधार पर छः वर्ष की अवधि के लिए सहायक अनुदान देने के लिए वचनबद्ध है। इस वचनबद्धता की पूर्ति की दिशा में पहले छः महीने के लिए 17.65 लाख रुपए का अनुदान समाचार एजेंसियो को पहले ही दिया जा चुका है। तथापि, समाचार और समाचार एजेंसियो के बीच कोई लिखित या मौखिक समझौता नही हुआ है।

Opening of Small Service Institute at Tirunelveli and Kanyakumari

3448. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government would examine the opening of Small Service Institute at Tirunelveli and Kanyakumari for the development of Small Scale and Rural Industries as these districts have immense agricultural and fishery resources; and

(b) whether Government would consider the establishment of a branch of SSI to facilitate intensive promotional work in the village and taluk levels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b) Under the present Industrial Policy, high priority is being given to the effective development of cottage and small industries which are dispersed in rural areas and small towns of the country. The focal point of development of small scale and cottage industries is shifting from cities and State capitals to the districts. To implement this Policy, district industries centre are being set up in every district according to a phased programme. This will facilitate intensive promotional work in the villages and at taluk levels. The Government of Tamil Nadu is setting up 8 D.I.Cs. with Central assistance and these will include Tirunelveli and Kanyakumari. The SISIs will provide full technical support to the DICs in the effective implementation of this programme.

Breaches at National Highway No. 7

3449. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on National Highway No. 7 between Hyderabad, and Nagpur at a distance of about 250 K.M. from Hyderabad, the road breaches at Kupthi Ghat